अभियान, सेमिनार करके लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और इसी तरह मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए मानव अधिकार कमीशन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बनाए गए हैं। बहुत-सी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। यह मानव अधिकार हनन क्यों होता है? वह तब होता है, जब कोई अपना कर्त्तव्य पूरा करे, इसके लिए जन-जन में अपना कर्त्तव्य पूरा करने की भावना पैदा की जाए, इसके लिए इस तरह का एक वातावरण तैयार करना होगा।

आज मानव अधिकारों के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाईयाँ अलग-अलग ढंग से लड़ी जा रही हैं, लेकिन अपने कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई मंच नहीं है, जो लोगों और अधिकारियों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए कोई मंच प्रदान कर सके। कुछ कार्यक्रम सिर्फ प्रयोजन हेतु हो जाते हैं, लेकिन वे सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लिए सक्षम नहीं होते। मानवता के प्रति लोगों की एवं अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी है, ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए देश भर में कोई दिन निश्चित हो। जिस प्रकार 10 दिसम्बर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि कोई एक दिन तय करे, जिसे राष्ट्रीय मानव कर्त्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। यह संदेश सारी दुनिया को भारत की धरती से दिया जाए और भारत इसका नेतृत्व करे। ऐसी सरकार से अपेक्षा है।

Demand to take immediate steps to hold elections for the vacant posts in local bodies in Lakshadweep

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala) : Sir, in the Union Territory of Lakshadweep, the authorities are violating the provisions of Panchayati Raj Act. The 73rd and 74th Constitutional Amendments mandate the authorities to fill the vacancies in local bodies within six months. But in Lakshadweep, the authorities are not holding elections to the vacant seats. In ward number 3 of Kavaratti Panchayat, the elected member resigned last year. The seat is vacant for more than a year. In Kalpeni Panchayat, the Chairperson, who was elected from ward number 5, has also resigned. This seat is also vacant for the last one year.

The administration of Lakshadweep is under the direct control of the Union Government. The responsibility of holding by-elections to the vacant posts rests with the Union Government. Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to hold elections to the vacant seats.

Demand to restore financial assistance to spinning sector under TUF Scheme in Maharashtra

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra) : Sir, Maharashtra is one of the largest producers of cotton which is grown in the backward regions of Vidarbha, Marathwada, etc. Maharashtra Government has announced new Textile Policy with an intention to process maximum cotton in these backward regions of the State. The new policy is applicable to textile projects approved under the TUF Scheme of the Government of India. Hence the extension of the TUF Scheme in present shape is completely beneficial to the cotton growers of the State. The re-structured TUF Scheme has been launched in April, 2011, after an evaluation by CRISIL. CRISIL has observed